पटना के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में।

आपराधिक अपील (एसजे) संख्या : 1231/2023

पुर्णिया जिला के बैसी थाना कांड संख्या : 91/2016 से उत्पन्न मामला।

= = = =

- इस मामले में, पुलिस अधिकारियों ने जब्त किए गए पदार्थों को तुरंत खोल दिया और उनके अनुसार, कुछ पैकेटों से 25–25 ग्राम के दो नमूने तैयार कर सील कर दिए गए। यह NDPS अधिनियम की धारा 52(A)(c) का पूर्ण उल्लंघन है। (पैरा 36)
- न्यायालय एक और महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता। जब्त सामग्री को कभी भी ट्रायल कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया, और हालांकि अभियोजन पक्ष बार–बार यह कहता रहा कि इसे "मलकाना" (सुरक्षा गोदाम) में जमा किया गया था, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया। जब्त की गई 215.400 किलोग्राम 'गांजा' की कथित बरामदगी न्यायालय में प्रमाणित नहीं हो पाई, और न ही इसे विधि अनुसार नष्ट किए जाने का कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया। (पैरा 37)
- अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सभी गवाह पुलिस अधिकारी थे। हालांकि, अभियोजन द्वारा पेश किए गए दो स्वतंत्र गवाहों ने जिरह के दौरान कहा कि पुलिस ने उन्हें यह नहीं बताया कि उनके हस्ताक्षर किस उद्देश्य के लिए लिए जा रहे हैं। गवाहों के हस्ताक्षर लिए गए, लेकिन उनके समक्ष पैकेट खोले, तौले और सील नहीं किए गए। यह स्पष्ट रूप से अभियोजन की जब्ती (seizure) की पूरी कहानी को झूठा साबित करता है। (पैरा 38)
- जब्त सामग्री को तौला नहीं गया और "मलकाना" में रखा गया। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह साबित हो कि प्रतिनिधि नमूने लेने के बाद पुलिस ने जब्त सामग्री को पुनः तौला। (पैरा 39)

अपील स्वीकृत की जाती है। (पैरा 44)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

= = = =

*संख्या है **सी. जी.–11. बी. बी.–1701 था , कुल 42 पैकेट** बरामद किए गए और वजन करने पर यह **215.400 किलोग्राम 'गांजा'** पाया गया।*

*(iii) इसके बाद उपर्युक्त दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में भौतिक तलाशी ली गई और **करणबीर सिंह** के कब्जे से तीन मोबाइल और 19,000/– नकद बरामद किए गए, जबकि दीपक कुमार राय से एक मोबाइल बरामद किया गया।*

(iv) सूचना देने वाले ने आगे आरोप लगाया कि इलेक्ट्रॉनिक माप उपकरणों द्वारा ली गई माप पर, वसूली/जब्ती इस प्रकार थीः

(i) 22 पैकेटों के पहले समूह में 2.770 किलोग्राम से 3.000 किलोग्राम 'गांजा' था;

(ii) 12 पैकेटों के दूसरे समूह में 3.820 से 5.730 किलोग्राम 'गांजा' था; और

(iii) 8 पैकेटों के तीसरे समूह में 7.130 किलोग्राम से 12.700 किलोग्राम था। 'गांजा';

(v) माप के बाद, सभी पैकेटों को अभियुक्त व्यक्तियों और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में जब्त कर लिया गया ।

(vi) उपयर्युक्त लिखित प्रतिवेदन के आधार पर, अपीलार्थी और एक अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, करणबीर सिंह को किशोर पाया गया और इस प्रकार, उनके मामले को अलग कर दिया गया। **आरोप–पत्र 31.10.2016** पर प्रस्तुत किया गया, **08.12.2016 पर संज्ञान** लिया गया और अपीलार्थी के खिलाफ **21.01.2017 पर आरोप** बनाए गए, जिसने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और इसके परिणामस्वरूप मुकदमा शुरू हुआ।

4. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 9 गवाहों से पूछताछ की। वे इस प्रकार हैंः

(i) अभियोजन पक्ष का गवाह –1–स्वामीनाथ साह

(ii) अभियोजन पक्ष का गवाह –2– सहायक अवर निरीक्षक लाल बाबू

(iii) अभियोजन पक्ष का गवाह –3–कालेश्वर

(iv) अभियोजन पक्ष का गवाह –4– बाबू लाल राय

(v) अभियोजन पक्ष का गवाह– 5–तारकेश्वर प्रसाद सिंह (सूचक)

(vi) अभियोजन पक्ष का गवाह –6–सुभाष चंद्र मंडल

(vii) अभियोजन पक्ष का गवाह –7–जितेंद्र राणा

(viii) अभियोजन पक्ष का गवाह –8–मो. रायसुल (स्वतंत्र गवाह)

(ix) अभियोजन पक्ष का गवाह –9–एम. डी. सरबर (स्वतंत्र गवाह)

5. अभियोजन पक्ष द्वारा दाखिल प्रदर्श इस प्रकार हैः

(I) प्रदर्श –1–जब्ती सूची

(ii) प्रदर्श –2–लिखित आवेदन।

(iii) प्रदर्श –3–औपचारिक प्रथम सूचना प्रतिवेदन।

(iv) प्रदर्श –4 और 4/ए– सूचना ।

(v) प्रदर्श –1/1 और प्रदर्श –1/2 –जब्त किए गए पैकेट 8 और 9 पर पर हस्ताक्षर ।

(vi) प्रदर्श –5–फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, पटना का प्रतिवेदन।

(vii) प्रदर्श – 6 –केन्द्रीय अभिलेख रखरखाव और नियंत्रण प्रयोगशाला, कोलकाता का प्रतिवेदन।

6. **अभियोजन पक्ष का गवाह – 1 स्वामीनाथ साह–** वे बैसी पुलिस थाना में सुरक्षित प्रहरी के रूप में सेवारत थे। उनके अनुसार, एक सफेद कार डालकोला की ओर से आ रही थी। पुलिस ने वाहन को रोकने की कोशिश की लेकिन चालक ने कार के साथ भागने के लिए एक मोड़ लिया। पुलिस ने उस वाहन का पीछा किया जो राष्ट्रीय राजमार्ग से निकलकर **सादिपुर भूटाहा गांव** में घुस गया, जहां आखिरकार उसे रोक लिया गया। वहाँ बैठे लोग अपीलार्थी और करणवीर सिंह थे। तीन मोबाइल और रुपये की बरामदगी/जब्ती हुई थी। 19, 000/– करणवीर सिंह से जबकि एक मोबाइल दीपक कुमार राय से। डिक्की की तलाशी लेने

पर, 215 किलोग्राम 400 ग्राम वजन के 'गांजा' जैसे पदार्थ के कुल 42 पैकेट बरामद किए गए। जब्ती सूची तैयार की गई, सील कर दी गई और तदनुसार जब्त कर लिया गया। अभियुक्तों को थाने ले जाया गया।

7. अपनी प्रतिपरीक्षा में, अभियोजन पक्ष का गवाह –1 ने कहा कि 'चौकीदार' बाबू लाल राय (अभियोजन पक्ष का गवाह –4) जब्त किए गए गांजे को तौलने के लिए तौल मशीन लाने गए थे। इसके अलावा, घटना स्थल पर ही नमूने तैयार किए गए, जिसके बाद, पैकेटों को फिर से सील कर दिया गया। बाद में इसे "मलखाना" में जमा कर दिया गया। यह पूछे जाने पर कि नमूनों पर कोई मुहर लगी थी या नहीं, उनके अनुसार, उनके पास जानकारी नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने स्वीकार किया कि जब्त गांजा को अदालत में पेश नहीं किया गया था।

8. **अभियोजन पक्ष का गवाह .–2–लाल बाबू राय** पुलिस के उप निरीक्षक हैं जिन्होंने वही कहानी सुनाई है। उनके अनुसार, हालांकि मुहर 'चौकीदार', बाबूलाल राय द्वारा पुलिस थाना से लाई गई थी, लेकिन इससे संबंधित दस्तावेज तैयार नहीं किया गया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जब्त की गई सामग्री अदालत में उपलब्ध नहीं है।

9. **अभियोजन पक्ष का गवाह –3– कालेश्वर पासवान** भी एक पुलिस सिपाही है जो बैसी पुलिस थाना में तैनात था। उन्होंने भी यही कहानी लिखी है। उनके अनुसार, वह छापा मारने वाली टीम का हिस्सा था और जब तक वे पुलिस थाना नहीं लौटे, तब तक उसके सामने सूचना देने वाले/ थानाध्यक्ष द्वारा कोई कागज तैयार नहीं किया गया था और न ही गांजे के नमूने लिए गए थे और न ही सील किए गए थे।

10. **अभियोजन पक्ष का गवाह –4 –बाबूलाल राय** 'चौकीदार' हैं जो अन्य गवाहों के अनुसार वे वजन करने वाली मशीन के साथ–साथ पुलिस स्टेशन से जब्त किए गए गांजे को सील करने से संबंधित सामग्री भी लाए थे। उन्होंने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन किया और आगे कहा कि जब्त की गई सामग्री को उनकी उपस्थिति में सील कर दिया गया था। उनके अनुसार, सभी 42 पैकेटों से नमूनों के तीन पैकेट तैयार किए गए थे।

11. **अभियोजन पक्ष का गवाह –5 –तारकेश्वर प्रसाद सिंह हैं, जो बैसी पुलिस थाना के सूचक सह स्टेशन प्रमुख अधिकारी हैं।** उनके अनुसार, वह मौके पर वाहन की जांच कर रहे थे। लगभग 2 बजेः30 एएम, उन्होंने डालकोला से आ रहा एक वाहन पाया और पुलिस को देखते ही वाहन ने पटरी बदल दी। अंततः इसे सादिपुर भूटाहा गाँव में रोक दिया गया। करणबीर सिंह और यह अपीलार्थी दीपक कुमार राय कार में मौजूद थे। इसके अलावा, दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में, मो. सरवर और मो. रायसुल, उनकी

तलाशी ली गई और मोबाइल और नकद राशि के अलावा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, कार के डिक्की से *गांजा* के 42 प्लास्टिक के पैकेट बरामद/जब्त किए गए।

12. अभियोजन पक्ष का गवाह –5– के अनुसार, तलाशी से पहले, अभियुक्तों को सूचित किया गया था कि वे राजपत्रित पुलिस अधिकारी या दंडाधिकारी की उपस्थिति के लिए अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन दोनों अभियुक्त संतुष्ट थे कि पुलिस अधिकारी द्वारा उनकी तलाशी ली जा सकती है। पुलिस ने 42 पैकेट बरामद/जब्त किए। यह वजन, 215.400 किलोग्राम *गांजा* और चूंकि कोई दस्तावेज नहीं था, इसलिए स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में उन्हें जब्त कर लिया गया। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई।

13. पैकेटों को तीन भागों में विभाजित किया गया था और 25 ग्राम की छोटी मात्रा को पैकेटों से दो नमूनों के रूप में लिया गया था जिन्हें फिर से सील कर दिया गया था। पुलिस स्टेशन लौटने के बाद, प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच सौंपी गई **सुभाष चंद्र मंडल** को **(अभियोजन पक्ष का गवाह –6)** जिन्होंने जब्ती सूची पर अपने हस्ताक्षर का पहचान किया ।

14. जिरह में, सूचक (अभियोजन पक्ष का गवाह– 5) ने कहा कि चूंकि उसने सुभाष चंद्र मंडल को जांच का प्रभार सौंप दिया था, इसलिए वह यह नहीं कह सकता कि जब्त की गई सामग्री को फिर से सील कर दिया गया था या नहीं। उनके अनुसार, वह हमेशा कागज, कलम और सीलबंद वस्तुओं के साथ घूमते थे और उस दिन भी वह उनके पास था। इसके अलावा, सभी 42 पैकेटों से नमूने नहीं लिए गए। उन्हें 1 से 42 तक गिना गया और तीन समूहों में रखा गया। वह अदालत को यह भी नहीं बता सके कि इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन कहाँ से लाई गई थी। वह स्वीकार करता है कि पुलिस स्टेशन में "मलखाना" रजिस्टर है लेकिन एस. डी. प्रविष्टि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं है। उक्त अभियोजन पक्ष ने स्वीकार किया कि जब्त की गई सामग्री को अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया था।

15. **अभियोजन पक्ष का गवाह –6 –सुभाष चंद्र मंडल** फिर से एक पुलिस अधिकारी (पुलिस उप–निरीक्षक) है जिन्हें जाँच का प्रभार दिया गया था। उनके अनुसार, उन्होंने पुलिस थाने में पुलिस गवाह लाल मोहन सिंह और हवालदार स्वामीनाथ साह का बयान लिया, जबकि स्वतंत्र गवाह मोहम्मद का बयान लिया। **मो. सरवर और मो. रायसुल** को घटना स्थल पर ही ले जाया गया था। उन्होंने अभियोजन पक्ष की कहानी का भी समर्थन किया है और कहा है कि जब्त की गई सामग्री को "मलखाना" में रखा गया था।

16. जिरह के दौरान, उन्होंने कहा कि उक्त घटना/बरामदगी/जब्ती से संबंधित कोई प्रतिवेदन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी। इसके अलावा, एस. एच. ओ. ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सूचित किया या नहीं, उन्हें नहीं पता। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि हालांकि जब्त

की गई सामग्री "मलखाना" में रखी गई थी, लेकिन विवरण डायरी में नहीं मिल सका। उन्होंने नमूनों को जांच के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में नहीं भेजा।

17. **अभियोजन पक्ष का गवाह –7 – जितेंद्र राणा** फिर से एक पुलिस उपनिरीक्षक– है । उन्होंने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन किया है और आगे कहा है कि जब्त किए गए नमूनों को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजने के लिए, उन्होंने जब्त की गई सामग्री के साथ खुद को प्रस्तुत किया और विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा 27.08.2016 पर दिए गए आदेश पर, नमूनों को **फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, पटना 13.09.2016 पर और C.R.C.L, कोलकाता 20.09.2016 पर भेजा ।**

18. उनके अनुसार, कार का मालिक छत्तीसगढ़ के **रमेश कुमार अग्रवाल** थे, जिनसे करणवीर सिंह ने इसे खरीदा था। उन्होंने आगे बताया कि इसमें अपीलकर्ता ने एक याचिका दी थी कि वह करणवीर सिंह का चालक था। जिरह के दौरान, उन्होंने स्वीकार किया है कि रमेश कुमार अग्रवाल का बयान नहीं लिया गया था और न ही उन्होंने जिला परिवहन कार्यालय से कार के पंजीकरण की जांच की थी। उन्होंने स्वीकार किया कि जब्त की गई सामग्री का उस समय वजन नहीं किया गया था, इसे "मलखाने" में रखा गया था।

19. **अभियोजन पक्ष का गवाह–8 – मोहम्मद रायसुल** एक स्वतंत्र गवाह है। हालाँकि उन्होंने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन किया है, लेकिन जिरह के दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें यह नहीं बताया कि किस कागज पर और किस उद्देश्य के लिए उनके हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं। इसके अलावा, पुलिस ने वजन के लिए पैकेट नहीं खोले और/या उनकी उपस्थिति में उन्हें सील कर दिया गया।

20. अंतिम गवाह **अभियोजन पक्ष का –9– मोहम्मद सरवर** हैं । उनके अनुसार, उन्हें पुलिस द्वारा एक कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था, लेकिन यह नहीं बताया कि यह किस उद्देश्य के लिए लिया गया है। उनके अनुसार, पुलिस ने उनके पटना उच्च न्यायालय सी. आर. में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। उपस्थिति। जिरह के दौरान, उन्होंने स्वीकार किया कि पुलिस ने उन्हें कभी सूचित नहीं किया कि किस उद्देश्य के लिए उनके हस्ताक्षर किए गए हैं और न ही उनकी उपस्थिति में पैकेट खोले गए, तौले गए और सील किए गए।

21. विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि उस समय, अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया था, स्थानीय लोग इकट्ठा हुए थे जिनसे मो. सरवर और मो. रसूल से स्वतंत्र गवाह के रूप में खड़े होने का अनुरोध किया गया था। इसके अलावा, आरोपी ने स्वीकार किया कि सभी पैकेटों में गांजा था और राजपत्रित अधिकारी की अनुपस्थिति में पुलिस अधिकारियों को उनकी तलाशी लेने की

अनुमति भी दी। इसके बाद स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तलाशी ली गई। बाद में, बाबूलाल राय को तौल मशीन लाने के लिए भेजा गया।

22. विचारण न्यायालय ने आगे दर्ज किया है कि एक बार मशीन के आने के बाद, जब्त की गई सामग्री का वजन किया गया था जो 215.400 किलोग्राम था। इसके बाद ऊपर वर्णित कानूनी प्रक्रिया और उनकी गिरफ्तारी हुई। ट्रायल कोर्ट ने विभिन्न प्रदर्शों पर भी ध्यान दिया है जो ऊपर शामिल हैं।

23. इसके बाद, निचली अदालत पक्षों को सुनकर इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आरोपी और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में डिक्की की तलाशी लेने पर, कुल 215.400 किलोग्राम गांजा बरामद/जब्त किया गया था। दोनों आरोपी कार में मौजूद थे। नमूनों को C.R.C.L, **कोलकाता** साथ ही **फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, पटना** भेजा गया और वहाँ के संबंधित प्रतिवेदनों ने पुष्टि की कि जब्त किए गए सामान **टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल** हैं जो **गांजा** है। उस पृष्ठभूमि में,न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अपीलार्थी दीपक कुमार राय के खिलाफ मामला धारा **20 (बी) (ii)(सी) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम ।** के तहत साबित हुआ है।

24. जैसा कि कहा गया है, करणवर सिंह के बारे में विद्वान अधिवक्ताओं के सवाल पर, यह सूचित किया गया है कि वह नाबालिग होने के कारण, उसका मामला अलग से लिया गया था।

25. तदनुसार, अपीलार्थी, दीपक कुमार राय को स्वापक औषधि और मन :प्रभावी पदार्थ अधिनियम' की धारा 20 (बी) (ii) (सी) के तहत दोषी ठहराया गया था और एक आदेश के अनुसार 10 साल के कठोर कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। 1,00,000–। जुर्माने का भुगतान न करने पर उन्हें छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। इसमें वह अवधि भी शामिल है जब वह न्यायिक हिरासत में रहे हैं।

26. व्यथित, वर्तमान अपील।

27. श्री मनोज कुमार द्वारा प्रस्तुत अपीलार्थी का मामला यह है कि पुलिस स्वापक औषधि और मन :प्रभावी पदार्थ अधिनियम' की विभिन्न धाराओं के अनुसार सख्ती से पालन/कार्य करने में विफल रही क्योंकि अपीलार्थी की तलाशी राजपत्रित अधिकारी/वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में नहीं की गई थी, बल्कि पुलिस अधिकारियों द्वाराकी गई थी,जो वहाँ उपस्थित थे । इसके अलावा, यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि यदि पुलिस ने तलाशी ली, तो वरिष्ठ अधिकारी को 72 घंटे की अवधि के

भीतर तुरंत सूचित किया गया जैसा कि स्वापक औषधि और मन :प्रभावी पदार्थ अधिनियम' के तहत अनिवार्य था।

28. यह उनका आगे का निवेदन है कि स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52 (ए) का भी उल्लंघन किया गया था क्योंकि जब्त की गई सामग्री के प्रतिनिधि नमूने दंडाधिकारी की उपस्थिति में नहीं लिए गए थे क्योंकि अभियोजन पक्ष की कहानी यह है कि जब्ती के तुरंत बाद, नमूने पैकेट खोलकर तैयार किए गए थे। नमूने निकाले जाने के बाद इसका वजन नहीं किया गया। इसके अलावा, न तो जब्त की गई वस्तुओं को निचली अदालत के समक्ष पेश किया गया और न ही यह दिखाने के लिए कोई रिपोर्ट/प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया कि उन्हें नष्ट कर दिया गया है। वह प्रस्तुत करते है कि उक्त तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि अपीलार्थी को मामले में फंसाया गया था जिसके परिणामस्वरूप उसे गलत तरीके से दोषी ठहराया गया और परिणामस्वरूप प्राथमिकी (20.06.2016) दर्ज करने की तारीख से हिरासत में लिया गया।

29. राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री अभय कुमार ने अभियोजन पक्ष की इस कहानी का समर्थन करने के लिए इस अदालत को स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम' की धारा 50 (5) में ले गए हैं कि राजपत्रित अधिकारी की अनुपस्थिति अभियोजन पक्ष की कहानी के लिए हानिकारक नहीं होगी। हालाँकि, यह पूछे जाने पर कि क्या उस मामले में, वरिष्ठ अधिकारियों को 72 घंटे की अवधि के भीतर सूचित किया जाना है जैसा कि **स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 की धारा 6** के तहत अनिवार्य है क्या कोई जानकारी दी गई थी, इसका उत्तर नकारात्मक है।

30. यह उनका अगला निवेदन है कि भारी मात्रा में 'गांजा' बरामद किया गया/जब्त किया गया, प्रतिनिधि नमूने निकाले गए, दो प्रतिष्ठित सरकारी प्रयोगशालाओं को परीक्षण के लिए भेजे गए, जिसने पुष्टि की कि जब्त की गई सामग्री 'गांजा' थी और उस पृष्ठभूमि में, निचली न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहुंची जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया/सजा सुनाई गई, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

31. इस न्यायालय ने पक्षकारों को सुना है और अभियोजन पक्ष की कहानी को भी देखा है। इस न्यायालय के समक्ष सवाल यह है कि क्या अभियोजन पक्ष निचली अदालत के समक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में सक्षम हुआ था।

32. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि उसने एक वाहन को रोका जिसने भागने की कोशिश की लेकिन अंत में उसे पकड़ लिया। व्यक्ति और डिक्की की तलाशी लेने पर, मोबाइल के बगल में

(अपीलार्थी से), 215.400 किलोग्राम 'गांजा' बरामद हुआ/था। अपीलार्थी को सूचित किया गया कि क्या दंडाधिकारी या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी ली जानी चाहिए और केवल दी गई सहमति पर, यह पुलिस द्वारा संचालित किया गया था। न्यायालय की राय में यह स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम' की धारा 50 को पूरा नहीं करता है जो राजपत्रित पटना उच्च न्यायालय सी. आर. की उपस्थिति में की जाने वाली तलाशी के बारे में बात करता है। अधिकारी या दंडाधिकारी। इसके अलावा, यदि यह संभव नहीं है, तो उसके तुरंत बाद और 72 घंटों के भीतर, तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को एक जानकारी भेजी जानी चाहिए जो कभी नहीं की गई थी, एक ऐसा तथ्य जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

33. सवप्वापक औषधि और मन:प्रभा प्रभावी पदार्थ अधिनियम' 1985 की धारा 50 को शामिल करना भी महत्वपूर्ण है जो ऐसे प्रावधानों से संबंधित हैः

> ***50. जिन शर्तों के तहत व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी***–*(1) कब। धारा 42 के तहत विधिवत अधिकृत कोई भी अधिकारी धारा 41, धारा 42 या धारा 43 के प्रावधानों के तहत किसी भी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है, वह, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसा चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक देरी के धारा 42 में उल्लिखित किसी भी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम दंडाधिकारी के पास ले जाएगा।*
>
> *(2) यदि ऐसी माँग की जाती है, तो अधिकारी उस व्यक्ति को तब तक हिरासत में रख सकता है जब तक कि वह उसे राजपत्रित अधिकारी या उप–धारा (1) में निर्दिष्ट दण्डाधिकारी के सामने नहीं ला सकता।*
>
> *(3) राजपत्रित अधिकारी या दण्डाधिकारी जिसके समक्ष ऐसे किसी व्यक्ति को लाया जाता है, यदि वह तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं देखता है, तो उस व्यक्ति को तुरंत आरोप मुक्त कर देगा, लेकिन अन्यथा यह निर्देश देगा कि तलाशी ली जाए।*
>
> *(4) एक महिला के अलावा किसी भी महिला की तलाशी नहीं ली जाएगी।*
>
> ***(5) जब धारा 42 के तहत विधिवत अधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति को किसी मादक पदार्थ या मादक पदार्थ, या नियंत्रित पदार्थ या वस्तु या दस्तावेज के साथ अलग***

होने की संभावना के बिना निकटतम राजपत्रित अधिकारी या दंडाधिकारी के पास तलाशी के लिए ले जाना संभव नहीं है, तो वह ऐसे व्यक्ति को आपराधिक प्रक्रिया संहिता ,1973 की धारा 100 के तहत निकटतम राजपत्रित अधिकारी या दंडाधिकारी के पास ले जाने के बजाय, व्यक्ति की तलाशी के लिए आगे बढ़ सकता है।

(6) उप–धारा (5) के तहत तलाशी लेने के बाद, अधिकारी ऐसे विश्वास के कारणों को दर्ज करेगा जिसके कारण ऐसी तलाशी की आवश्यकता पड़ी और बयालीस घंटे के भीतर उसकी एक प्रति अपने तत्काल अधिकारी वरिष्ठ को भेजेगा।

34. इसके अलावा, 'एन. डी. पी. एस. अधिनियम' के 52 ए को इस रूप में पढ़ा जाता है, निम्नलिखित है:

52 ए. जब्त मादक पदार्थों और मनोदैहिक पदार्थों का निपटान : *(1) केंद्र सरकार, खतरनाक प्रकृति, चोरी की भेद्यता, प्रतिस्थापन, उचित भंडारण स्थान की बाधा या किसी अन्य प्रासंगिक विचार को ध्यान में रखते हुए, किसी भी मादक दवाओं, मनोदैहिक पदार्थों, परिवहन के नियंत्रित पदार्थों के संबंध में, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी मादक दवाओं, मनोदैहिक पदार्थों, नियंत्रित पदार्थ या परिवहन या मादक पदार्थों का वर्ग, मादक पदार्थों का वर्ग, नियंत्रित पदार्थों का वर्ग या परिवहन, जिनका जब्ती के बाद जितनी जल्दी हो सके, ऐसे अधिकारी द्वारा निपटान किया जाएगा और इस तरह से कि सरकार समय–समय पर इसके बाद निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के बाद निर्धारित करे।)*

(2) जहां किसी भी (मादक पदार्थ, मादक पदार्थ, नियंत्रित पदार्थ या परिवहन) को जब्त कर लिया गया है और निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या धारा 53 के तहत सशक्त अधिकारी को भेज दिया गया है, तो उप–धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी ऐसी "मादक पदार्थों, मादक पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या परिवहन" की एक सूची तैयार करेगा। उनके विवरण, गुणवत्ता, मात्रा, पैकिंग का तरीका, निशान, संख्या या

मादक दवाओं, मादक पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या परिवहन के ऐसे अन्य पहचान विवरण) या उस पैकिंग जिसमें वे पैक किए गए हैं, मूल देश और अन्य विवरणों से संबंधित विवरण, जैसा कि उप–धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में (मादक दवाओं, मादक पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या परिवहन) की पहचान के लिए प्रासंगिक विचार कर सकता है और इस उद्देश्य के लिए किसी भी मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है –

(क) इस प्रकार तैयार की गई सूची की शुद्धता को प्रमाणित करना, या

(ख) ऐसे दंडाधिकारी की उपस्थिति में, ऐसी दवाओं, पदार्थों या परिवहन की तस्वीरें लेना) और ऐसी तस्वीरों को सत्य के रूप में प्रमाणित करना, या

(ग) ऐसे दंडाधिकारी की उपस्थिति में ऐसी दवाओं या पदार्थों के प्रतिनिधि नमूने लेने की अनुमति देना और इस तरह से तैयार किए गए नमूनों की किसी भी सूची की शुद्धता को प्रमाणित करना।

(3) जहाँ उप–धारा (2) के तहत कोई आवेदन किया जाता है, मजिस्ट्रेट, जितनी जल्दी हो सके, आवेदन को स्वीकार करेगा।

(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1972 का 1) या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम के तहत अपराध की सुनवाई करने वाला प्रत्येक न्यायालय, सूची, (मादक दवाओं, मादक पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या परिवहन) की तस्वीरों और उप–धारा (2) और पटना उच्च न्यायालय सी. आर. के तहत तैयार किए गए नमूनों की किसी भी सूची पर विचार करेगा। दंडाधिकारी द्वारा प्रमाणित, ऐसे अपराध के संबंध में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में।]

35. इस न्यायालय ने **'एन. डी. पी. एस. अधिनियम' की धारा 52 (ए) (सी)** दर्ज की है जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि प्रतिनिधि दंडाधिकारी की उपस्थिति में लिए जाने हैं जो इसकी शुद्धता को प्रमाणित करेगा जिसके लिए उसके समक्ष एक उचित आवेदन प्रस्तुत किया जाना है।

36. यह एक ऐसा मामला है जिसमें पुलिस अधिकारियों ने जब्ती के तुरंत बाद जब्त की गई वस्तुओं को खोला, उनके अनुसार, कुछ पैकेटों से दो नमूनों में से प्रत्येक को 25 ग्राम तैयार किया गया था, जिसके बाद उसे सील कर दिया गया था। यह एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52 (ए) (सी) का पूरी तरह से उल्लंघन था।

37. यह न्यायालय एक अन्य तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। जब्त की गई सामग्री को कभी भी निचली अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया और हालांकि अभियोजन पक्ष ने बार–बार कहा कि इसे "मलखाना" में जमा किया गया था, यहां तक कि उनके द्वारा की गई प्रविष्टि भी प्रदान नहीं की जा सकी। जब्त की गई सामग्री के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने और/या किसी भी प्रमाण पत्र के अभाव में जो यह दर्शाता है कि इसे कानून के अनुसार नष्ट कर दिया गया है, 215.400 किलोग्राम 'गांजा' की जब्ती की पूरी कहानी गिर जाती है।

38. इस मामले में, जबकि सभी गवाह पुलिस पटना उच्च न्यायालय सी. आर. हैं। अधिकारी, अभियोजन पक्ष द्वारा स्वतंत्र गवाहों के रूप में प्रस्तुत दो गवाह अर्थात् **अभियोजन पक्ष का गवाह संख्या –8, मो. रायसुल** और **अभियोजन पक्ष का गवाह संख्या – 9,** मो. सरबर ने जिरह के दौरान गवाही दी है कि पुलिस ने उन्हें सूचित नहीं किया कि किस उद्देश्य के लिए उनके संबंधित हस्ताक्षर कागज पर लिए गए हैं। **अभियोजन पक्ष का गवाह संख्या – 8** के अनुसार, **मो. रायसुल,** पुलिस ने वजन के लिए पैकेट नहीं खोले और/या उनकी उपस्थिति में उन्हें सील कर दिया गया। **अभियोजन पक्ष का गवाह संख्या –9, मोहम्मद सरबर** ने भी यही बयान दिया है कि हालांकि उनके हस्ताक्षर लिए गए थे, लेकिन उनकी उपस्थिति में पैकेट नहीं खोले गए, तौले नहीं गए और उन्हें सील नहीं किया गया। यह स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष के पूरे जब्ती सिद्धांत को गलत साबित करता है।

39. यहां पर अभियोजन पक्ष का गवाह संख्या – 7 के बयान पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है, जिन्होंने कहा था कि जब्त की गई सामग्री का वजन नहीं किया गया था और इसे "मलखाना" में रखा गया था। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि प्रतिनिधि नमूने निकाले जाने के बाद पुलिस ने फिर से जब्त की गई सामग्री का वजन किया।

40. के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय **भारत संघ बनाम मोहनलाल और एक अन्य (2016) 3** में रिपोर्ट किया गया: एस. सी. सी. 379 ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन के अभाव में **'एन. डी. पी. एस. अधिनियम' की धारा 52 (ए)** का पालन करने पर अभियुक्त राहत का हकदार है। पैराग्राफ संख्या–**14–17 मोहनलाल (ऊपर)** मामले को शामिल करना उचित होगा जो इस प्रकार हैं:

> ***14.*** *2014 के अधिनियम 16 द्वारा संशोधित धारा 52–ए जब्त की गई दवाओं और मादक पदार्थों के निपटान से संबंधित है। इसमें लिखा है:*
>
> *"**52–ए.** जब्त मादक पदार्थों और मनोदैहिक पदार्थों का निपटान। (1) केंद्र सरकार, किसी भी मादक पदार्थों या मादक पदार्थों की खतरनाक प्रकृति, चोरी की उनकी संवेदनशीलता, प्रतिस्थापन, उचित भंडारण स्थान की बाधाओं या किसी अन्य प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुए, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा कर सकती है। ऐसी मादक दवाओं या मनोदैहिक पदार्थों या मादक दवाओं के वर्ग या मनोदैहिक पदार्थों के वर्ग को निर्दिष्ट करें जो उनकी जब्ती के बाद जितनी जल्दी हो सके, ऐसे अधिकारी द्वारा और इस तरह से निपटाया जाएगा कि सरकार समय–समय पर इसके बाद निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के बाद निर्धारित करे।*
>
> *(2) जहां किसी भी मादक पदार्थ या मादक पदार्थ को जब्त कर लिया गया है और निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या धारा 53 के तहत सशक्त अधिकारी को भेज दिया गया है, वहां उप–धारा (1) में संदर्भित अधिकारी ऐसी मादक पदार्थों या मादक पदार्थों की एक सूची तैयार करेगा जिसमें उनके विवरण, गुणवत्ता, मात्रा, पैकिंग के तरीके, निशान, संख्या या मादक पदार्थों या मादक पदार्थों या मादक पदार्थों की ऐसी अन्य पहचान करने वाले विवरण या पैकिंग, जिसमें वे पैक किए गए हैं, मूल देश और अन्य विवरणों से संबंधित विवरण होंगे। उप–धारा (1) में निर्दिष्ट इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में मादक दवाओं या मादक पदार्थों की पहचान के लिए प्रासंगिक विचार कर सकता है और किसी भी दंडाधिकारी को इस उद्देश्य के लिए आवेदन कर सकता है–*

(ए) इस तरह से तैयार की गई सूची की शुद्धता को प्रमाणित करना; या (बी) ऐसे दंडाधिकारी की उपस्थिति में, ऐसी दवाओं या पदार्थों की तस्वीरें लेना और ऐसी तस्वीरों को सच के रूप में प्रमाणित करना; या

(ग) ऐसे दंडाधिकारी की उपस्थिति में ऐसी दवाओं या पदार्थों के प्रतिनिधि नमूने लेने की अनुमति देना और इस तरह से तैयार किए गए नमूनों की किसी भी सूची की शुद्धता को प्रमाणित करना। (3) जब उप–धारा (2) के तहत कोई आवेदन किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट, जितनी जल्दी हो सके, आवेदन की अनुमति देगा।

***(4)** इसके बावजूद भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में निहित कुछ भी, इस अधिनियम के तहत अपराध की सुनवाई करने वाला प्रत्येक न्यायालय, मादक पदार्थों की सूची, तस्वीरों पर विचार करेगा। मनःप्रभावी पदार्थ, नियंत्रित पदार्थ या परिवहन और उप–धारा (2) के तहत तैयार किए गए नमूनों की कोई सूची और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित, ऐसे अपराध के संबंध में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में"*

***15.** धारा 52–ए (2) (सी) (उपर्युक्त) से यह स्पष्ट है कि प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती पर उसे या तो निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या धारा 53 के तहत सशक्त अधिकारी को भेजा जाना चाहिए जो पटना उच्च न्यायालय सी. आर. के रूप में एक सूची तैयार करेगा। उक्त प्रावधान में निर्दिष्ट किया गया है और (क) सूची की शुद्धता को प्रमाणित करने (ख) दंडाधिकारी के समक्ष ली गई ऐसी दवाओं या पदार्थों की तस्वीरों को सही के रूप में प्रमाणित करने, और (ग) दंडाधिकारीकी उपस्थिति में प्रतिनिधि नमूने लेने और इस तरह से तैयार किए गए नमूनों की सूची की शुद्धता को प्रमाणित करने के उद्देश्यों के लिए दंडाधिकारी को आवेदन करें।*

16 धारा 52–ए की उप–धारा (3) में यह अपेक्षा की गई है कि दंडाधिकारी जितनी जल्दी हो सके आवेदन की अनुमति देगा। इसका तात्पर्य यह है कि जल्द ही जब्ती प्रभावी नहीं होती है और प्रतिबंधित पदार्थ को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या अधिकार प्राप्त अधिकारी को भेज दिया जाता है, तो संबंधित अधिकारी पटना उच्च न्यायालय सी. आर. सहित ऊपर उल्लिखित उद्देश्यों के लिए दंडाधिकारी से संपर्क करने के लिए कानूनी रूप से कर्तव्यबद्ध है। उसकी उपस्थिति में प्रतिनिधि नमूने लेने की अनुमति देना जिसके बाद कौन से नमूने सूचीबद्ध किए जाएंगे और मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रकार प्रमाणित नमूनों की सूची की शुद्धता दूसरे शब्दों में, नमूने लेने की प्रक्रिया दंडाधिकारी की उपस्थिति में और पर्यवेक्षण में होनी चाहिए और पूरी प्रक्रिया को सही होने के लिए उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

17. जब्ती के समय नमूने लेने का सवाल, जो अक्सर दंडाधिकारी की अनुपस्थिति में होता है, उपरोक्त योजनाओं में नहीं आता है। यह विशेष रूप से तब होता है जब अधिनियम की धारा 52–4 (4) के अनुसार, उपरोक्त धारा 32–ए की उप–धारा (2) और (3) के अनुपालन में दंडाधिकारी द्वारा तैयार और प्रमाणित नमूने मुकदमे के उद्देश्य के लिए प्राथमिक साक्ष्य का गठन करते हैं। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो जब्ती के समय नमूने लेने को अनिवार्य करता है। शायद यही कारण है कि कोई भी राज्य जब्ती के समय नमूने लेने का दावा नहीं करता है।

42. उपर्युक्त तथ्यों को शामिल करने के साथ–साथ **मोहनलाल** (उपर्युक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को भी शामिल करने के बाद, यह न्यायालय सुरक्षित रूप से मानता है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार है।

43. तदनुसार, विद्वत अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश–I, पूर्णिया द्वारा विशेष मामला सं.**02/2016/सी. आई. एस. No.01/2016 (बैसी पी. एस. केस नं. 91/2016)** मे पारित दिनांक 13–01–23 के दोषसीढ़ी आदेश और दिनांक 16–01–23 के सजा के आदेश जिसमे एकल अपीलार्थी से

संबंधित ' सवाप्वापक औषधि और मन :प्रभावी पथदार्थ अधिनियम की धारा 20 (ख) ((ii) (ग) के तहत अपराध जिसके लिए दस साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने का निर्देश दिया गया है उसे अपास्त किया जाता है।

44. अपील (एसजे) संख्या : 1231/2023 कोअनुमति दी जाती है और अपीलार्थी सभी आरोपों से बरी हो जाता है।

45. अपीलार्थी हिरासत में है। यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए।

46. अपील की अनुमति है।

(राजीव रॉय, जे)

रवि/–

खंडन (डिस्क्लेमर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।